International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 1; Issue 9; September 2016; Page No. 48-50

भारत के प्रति चीन का नवीन दृष्टिकोण

डॉ0 सुमन यादव

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

फरवरी, 1972 ई0 में पौलैण्ड में चीन के राजदूत ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की। इसके बाद 15 अगस्त, 1972 ई0 को लाल किला के समारोह में चीनी दूतावास के कुछ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, लेकिन इस उपस्थिति का कोई राजनीतिक अर्थ नही निकाला जा सकता। शिमला समझौते के बावजूद भारत के प्रति चीन के रवैये में कोई परिवर्तन नही हुआ। चीन यह मानकर चलता है कि भारत सोवियत संघ के द्वारा चीन को घेरा रहा है। 1974 ई0 में भारत सरकार की रिपोर्ट में चीन के साथ सम्बन्धो के सामान्य बनाने की भारत की तीव्रता के बावजूद चीन की प्रतिक्रिया अनुकूल नही रही है।

चीन ने 1975 ई0 मे कहा कि भारत की सिक्किम सम्बन्धी नीति ठीक नही है। कुछ ही दिनो के उपरान्त बर्फ पिघली। पिंगपांग के चीन टीम की भारत यात्रा (फरवरी, 1975 ई0) और दो–एक भारतीय पक्षकारो को चीन यात्रा के बाद भारत और चीन के बीच राजदूत स्तर पर राजनीतिक सम्बन्ध कायम करने के उद्देश्य से मंत्रणा प्रारम्भ हुई और अप्रैल, 1976 ई0 में भारत ने पेकिंग में अपना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी। के0 आर0 नारायणन् को इस पद पर तत्काल नियुक्त किया गया। चीन ने भी भारत में भी अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। 1977 ई0 में दो बार कैंटन में आयोजित उद्योग–मेलों में भारत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ऐसे में फरवरी 1978 ई0 में एक चीनी व्यापारिक शिष्टमंडल आया जिसने भारत के प्रमुख उद्योग केन्द्रो की यात्रा की। सत्रह वर्ष के बाद पहली दफा लेन–देन की शुरूवात हुई। चीन ने भारत से पाँच करोड़ रूपये के इस्पाती नल और एक करोड़ साठ लाख टन का कच्चा लोहे खरीदने के और भारत को पैतीस करोड़ रूपया का पारा, बीस लाख रूपये का जस्ता और एकतीस लाख रूपये का ऐंटीमन बेचने को करार किया। चीन ने भारत को अखबारी कागज देने का भी वादा किया। सितम्बर, 1976 ई0 में माओ–से–तुंग की मृत्यु हो गयी उनके स्थान पर कुओ फेग चीन के राष्ट्रपति बनाये गये। उस समय से लगभग डेढ़ वर्ष तक चीन में लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। मार्च, 1977 ई0 में मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता सरकार ने कहा कि वह सच्चे अर्थ में गुटनिरपेक्षता का अवलम्बन करेगी। 5 अगस्त, 1977 ई0 को भारत के विदेशमंत्री अटल विहारी बाजपेयी ने कहा कि भारत चीन के साथ है। स्वतन्त्रता उपरान्त भारत और पाकिस्तान के मध्य ''कश्मीर अत्यन्त ज्वलन्त समस्या के रूप में विद्यमान रहा है।'' एक भारतीय दल जून–जुलाई, 1977 ई0 में चीन गया और उच्च अधिकारियों से भेंट की। चीन ने तिब्बत एवं लामा को पृथक् करने का आरोप लगाया। चीन ने सितम्बर, 1978 ई0 में जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध नेता सुब्रहमण्यम् स्वामी को चीन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। फरवरी, 1979 ई0 में अटल भी चीन पहुचे। चीनी नेता भारत–चीन सीमा विवाद पर बातचीत करने को तैयार हुऐ। चीन ने कहा कि भारत कम्बोडिया में वियतनाम द्वारा की जा रही कारवाई की निन्दा करे। लगभग इसी समय संसद में सोवियत प्रधानमंत्री ने चीन की निन्दा की तो इस पर जोर से तॉलिया बजी। जुलाई, 1981 ई0 में विदेश मंत्री हुयांग हुआ भारत आये। भारतीय विदेश मंत्री नरसिंह राव ने हुआंग हुआ कि तीन दिन की बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय सभी मामलो पर विचार हुआ। इसमें भारतीयो को कैलाश मानसरोवर जाने की स्वतन्त्रता मिली। 31 अक्टूबर, 1985 ई0 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या कर दी गई और राजीव गाँधी भारत के नये प्रधानमंत्री बने। गाँधी ने भी स्पष्ट कहा कि हम लोग अच्छे सम्बन्ध के लिए प्रयास करेंगे और यदि बेहतर नही तो 1950 ई0 में जैसा सम्बन्ध था वैसा बनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। भारत–चीन वार्ता 4 नवम्बर, 1985 ई0 से 11 नवम्बर, 1985 ई0 तक चला। परन्तु दोनो पक्षों ने वार्ता के अन्त में कहा कि ''यह उपयोगी तथा दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए अनुकूल रही।''

दोनो पक्षो के बीच वार्ता का सॉतवा दौर 21 जुलाई, 1986 ई0 से शुरू होना निश्चित हुआ, परन्तु चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में घुसपैठ से दोनो के बीच सम्बन्ध एक बार फिर कटु होने की स्थिति में पहुँच गया। 18 जुलाई, 1986 ई0 को विदेश मंत्री शिवशंकर ने लोकसभा में स्पष्ट कहा कि अरूणाचल में चीनियों की घुसपैठ का मामला पेइचिंग में 21 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली अधिकारी स्तर की बैठक में उठाया जाएगा। 14 जुलाई, 1986 ई0 को ही अरूणाचल प्रदेश के इस इलाके में चीन ने अपनी फौजी चौकियाँ भी कायम कर ली। 85,806 वर्गमील 222,337 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में विस्तृत तनाव के इसी माहौल में बीजिंग में 21 जुलाई, 1986 ई0 को भारत और चीन के बीच अरसे से चले आ रहे सीमा विवाद पर सातवे दौर की बातचीत हुई। भारत का प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश सचित ए0 पी0 बेंकटेश्वर तथा चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के विदेश सचिव ल्यू शुहिंग ने किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को तीन अलग–अलग समूह में बाँट दिया गया जो सीमा विवाद, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा विज्ञान एवं तकनीकी सम्बन्ध में बातचीत करते रहे। विज्ञान एवं तकनीकी उपदल ने 1985 ई0 से बचे हुए पारस्परिक यात्रा कार्यक्रमो को जारी रखने का निश्चय किया। 1986 ई0 में चीन ने भारत पर चीनी सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया। जिसका भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अरूणाचल प्रदेश में चीनी हैलीपैड भी मौजूद है। 21 फरवरी, 1986 ई0 को अरूणाचल प्रदेश पर चीन ने फिर दावा किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ताजा वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि ''यह दोनो देशो के बीच सीमा पर शान्ति और सद्भाव बनायें रखने के आपसी समझ के खिलाफ है।'' जून, 1987 ई0 में भारत के विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने चीन की यात्रा की। आठवें दौर की वार्ता 15 नवम्बर, 1987 ई0 को शुरू हुई। चीन के विदेश उपमंत्री ल्यूसिंग ने चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, भारत के विदेश सचिव के0 पी0 एस0 मेनन ने भारत का नेतृत्व किया। नई दिल्ली में होने वाली आठवें दौर की वार्ता 17 नवम्बर, 1987 ई0 को बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गयी। जम्मू–कश्मीर 1981 ई0 के भारतीय आंकड़े के अनुसार 59,27,389

जनसंख्या से युक्त।

28 मई, 1988 ई0 को भारत और चीन के बीच पहली सांस्कृतिक संधि पर हस्ताक्षर हुई, यह समझौता 5 वर्ष के लिए हुई और आपत्ति न होने पर इसका स्वतः 5–5 वर्ष के लिए नवीनीकरण होता रहेगा। इसके अनुसार प्रायः दो वर्ष में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल एक–दूसरे देश की यात्रा करेंगे। जून, 1988 ई0 में पश्चिम बंगाल के मुखमंत्री ने चीन एवं जापान की यात्रा से लौटने के बाद बताया कि चीन ने बदलती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण चीन सरकार के भारत के प्रति रूख अच्छा है। राजीव गाँधी की चीन यात्रा को अन्तिम रूप देने के लिए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नवम्बर, 1988 ई0 के तीसरे सप्ताह में चीन पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयो और जटिल सीमा विवाद के बारे में चीनी नेताओं के साथ होने वाली प्रधानमंत्री की कार्यसूची पर चर्चा की। चीन की भूमि पर पैर रखते ही राजीव गाँधी ने कहा ''मै आशावान हूँ कि इसका परिणाम अच्छा निकलेगा।''

अपने पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान राजीव गाँधी ने साम्यवादी दल के चेयरमैन तथा चीन के वयोवृद्ध नेता देंग श्याओ पिंग, दल के महासचिव चाओ चिआंग राष्ट्रपति यांग शांकुन और प्रधानमंत्री ली पेंग से मुलाकात की। अमेरिका तथा जापानी सरकारो ने इसे सर्वाधिक अवधि तक हाथ मिलाये जाने की घटना कहा। सीमा विवाद पर संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया, और आर्थिक सम्बन्धों तथा व्यापार एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी। सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्यकारी दल में भारतीय विदेश सचिव तथा चीन के विदेश कार्य के उपमंत्री होगें। यह दल दो बाते सुनिश्चित करने का प्रयास करेगाः–

(1) नियंत्रण रेखा के साथ–साथ शांति बनाए रखना तथा

(2) दीर्घकाल से लम्बित सीमा विवाद का बातचीत द्वारा समाधान।

22 दिसम्बर, 1988 ई0 को भारत तथा चीन ने नागरिक उड्डयन सेवाओं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चस्तरीय सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें दोनो देश सीधे दिल्ली–बीजिंग के लिए विमान सेवाओं पर सहमत हो गये। यह अत्याधिक प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पन्न भू–भाग है। प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने पंचशील में आस्था व्यक्त करते हुए चीन यात्रा के परिप्रेक्ष्य में 23 दिसम्बर, 1988 ई0 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें सीमा विवाद के उचित तर्कसंगत और आपस में मान्य हल के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। संयुक्त विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया कि पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर ही दोनो पडोसी देशो के सम्बन्धों की बहाली और विकास न केवल दोनों देशों की जनता के हितो के अनुकूल है बल्कि इससे एशिया और पूरे विश्व में शांति और स्थिरता कायम करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री खाली हाथ वापस आये है। सोवियत संघ ने राजीव गाँधी की चीन यात्रा पर संतोष व्यक्त किया।

चीन के साथ सम्बन्ध सुधार की जिस प्रक्रिया की शुरूवात राजीव गाँधी ने 1988 ई0 में चीन यात्रा से किया था उसे बरकरार रखा। सितम्बर, 1993 ई0 में उन्होने चीन की यात्रा की इस यात्रा के दौरान वास्तविक सैनिक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाये रखने, सीमावर्ती व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढाने सम्बन्धी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। दिल्ली स्थित विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र के निदेशक और भारत के सबसे जानकार चीनी विशेषज्ञ गिरी देवी शंकर का यही विचार है कि ''देंग, माओ की पीढ़ी के उन बचे हुए लोगों में है जिन्होने लम्बी कूच और सांस्कृतिक क्रान्ति से लेकर खुलेपन की नीति के दौर देखे है। दुनियां की नजर मे वे बहुत धैर्यवान व्यक्ति है और बेहतर यही है कि उनके सत्ता में होते ही बातचीत कर ली जाय। जून, 1999 ई0 में विदेश मंत्री ने चीन यात्रा की। अप्रैल, 1999 ई0 में संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई। द्विपक्षीय वार्ता (Political Statement) तथा सुरक्षा संवाद पर चर्चा सम्पन्न हुई। जुलाई, 2000 ई0 में चीनी विदेशमंत्री की भारत यात्रा। दोनो पक्ष प्रथम चरण के समझौते को लागू करवाने के पक्ष में थे, जो कि मध्य खण्ड से शुरू होता है, तत्पश्चात पूर्वी खण्ड एवं पश्चिमी खण्ड तक जाता है। अप्रैल Golden Jubilee Celebration 2000 को मनाया गया। पीर पंजाब की पर्वत मालाओं में नौ हजार फीट की ऊंचाई वाले पर्वत को पार करते ही कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वारा आ जाता है और जवाहर टनल को पार करते ही घाटी के अनन्तनाग शहर है, जिसके उत्तर दिशा में बड़ग्राम नीचे की तरफ बारामूला और दांई तरफ कूपवाड़ा जिले आते हैं।

आडवाणी जी चीन गये थे मई – जून, 2000 ई0 को भारतीय राष्ट्रपति के0 आर0 नारायणन चीन की यात्रा पर गये परिणामस्वरूप समस्त द्विपक्षीय विवादो को हल करने के लिए प्रभुत्व व्यक्तियों के समूह (Eminent person groups - EPG) का निर्माण किया गया। भारत चाहता था कि सीमा विवाद को शीघ्र हल करे तथा चीन–पाक मिसाइल सम्बन्धों पर चिन्ता व्यक्त की। जनवरी, 2001 ई0 को ली पेंग का भारत आगमन तथा जनवरी, 2002 ई0 में झू रोंग जी का भारत आगमन इसमें आर्थिक एवं आधुनिकीकरण की एकता पर विचार किया गया। चीन शिमला समझौते को मानता है लेकिन चीन जम्मू–कश्मीर को मुख्य मुद्दा मानता है। जबकि अमेरीका जम्मु–कश्मीर को विवाद मानता है। मार्च, 2002 ई0 में जसवंत सिंह की यात्रा पर पश्चिमी खण्ड पर मानचित्र का आदान–प्रदान संभव हुआ जबकि मध्य क्षेत्र पर फैसला हो चुका है। जुलाई, 2003 ई0 में अटल बिहारी बाजपेयी की चीन यात्रा में भारत कहता है कि तिब्बत स्वायत क्षेत्र है। भारत कहता है कि जो जनवादी चीन का अंग है वहाँ तिब्बतियों को चीन विरोधी कार्यवाही में संलिप्त होने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नही किया जायेगा। 'विशिष्ट प्रतिनिधियों का संयुक्त घोषणा' के अर्न्तगत राजनीतिक हल खोजा जायेगा। भारत बहुध्रुवीय पक्ष को मानता है चीन भी इसे मानता है। दोनों देश ने भौगोलिक प्रक्रिया को सकारात्मकता का सिद्धान्त दिया है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से यह भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तिब्बत की स्थिति

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में बहुत वर्षो तक भारत–चीन का सम्बन्ध अत्यन्त अच्छा रहा; फिर भी एक प्रश्न पर दोनों के बीच आरम्भ से ही मतभेद की स्थिति पायी जाती है और यह प्रश्न तिब्बत से सम्बन्धित था। तिब्बत चीन और भारत के बीच स्थित है और इस पर चीन की सर्वोच्च सत्ता बहुत पहले से रही है। साथ ही, बहुत प्राचीन काल से इसके साथ भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध चला आ रहा है। (बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से जब तिब्बत पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा तो भारत ब्रिटिश सरकार सशंकित हुई लार्ड कर्जन ने 1905 ई0 में एक सैनिक दस्ता भेज दलाई लामा को एक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।) 1906 ई0 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक सन्धि हुई जिसके द्वारा ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया। इस सन्धि के द्वारा ही यह तय हुआ कि तिब्बत की राजधानी लहासा में एक भारतीय एजेन्ट रहेगा। याँटूग, ग्यान्टसे और गारटोक में भारत की व्यापारिक एजेंसियाँ कायम की जायँगी तथा ग्यान्टसे तक डाक–तार घर स्थापित करने का अधिकार भी भारत को रहेगा। इससे अधिक इसकी स्थिति भारत, पाकिस्तान, चीन के प्रान्त तिब्बत तथा सिक्यांग और अफगानिस्तान

द्वारा नियंत्रित संकुचित बखान पट्टी से बढ़कर सोवियत संघ तक इसकी भारतीय तथा पाकिस्तान नेताओं की दृष्टि में सामरिक महत्व से युक्त करती थी। इन सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को अपने व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए तिब्बत में कुछ सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन इस सन्धि में एक महत्वपूर्ण बात थी, इसमें कहीं भी तिब्बत और चीन में सम्बन्धों का स्पष्टीकरण नही किया गया था। वास्तविक बात यह थी कि आन्तरिक मामले के तिब्बत हमेशा से पूर्ण स्वाधीन रहा है यद्यपि चीन की सर्वोच्च सत्ता उस पर रही है। फिर भी, चीन को जब–जब मौका मिला है उसने तिब्बत की स्वायत्तता नष्ट करके उसे अपना, अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया है। इस तरह का दावा चीन ने हमेशा प्रस्तुत किया। जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो तिब्बत की सरकार लहासा के कोमितांग मिशन को हटाने का प्रयास करने लगी। तिब्बत के इस प्रयास को चीन की नयी सरकार ने शंका की दृष्टि से देखा और समझा की वह अपने को चीनी प्रभाव से मुक्त करना चाहता है। अतएव, चीन ने उस पर अपना दावा किया। 1 जनवरी, 1950 ई0 को चीन ने ''तिब्बत को साम्राज्यवादी षड्यंत्र से मुक्ति दिलाने'' की घोषणा की। भारत ने चीन द्वारा तिब्बत के प्रति इस नीति का विरोध किया। भारत तिब्बत में अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार था। तिब्बत में चीन सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने को तैयार था, परन्तु साथ ही यह भी चाहता था कि उसे एक स्वायत्त शासन प्राप्त इकाई का स्थान प्रदान किया जाय। लेकिन, चीन ने इसकी कोई परवाह नही की और 25 अक्टूबर, 1950 ई0 को तिब्बत के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही शुरू कर दिया। जब भारत ने इस सशस्त्र कार्यवाही का विरोध किया तो उत्तर में चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह साम्राज्यवादियों के बहकावें में आकर चीन के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इस वातावरण मे थोड़े समय के लिए चीन और भारत के सम्बन्ध में तनाव आ गया, लेकिन स्थिति अधिक दिनों तक नही रही। 23 मई, 1951 ई0 को चीन और तिब्बत में एक समझौता हो गया। इसके अनुसार, यह निश्चय हुआ कि तिब्बत का वैदेशिक सम्बन्ध, व्यापार, सुरक्षा और आवागमन पर चीन का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा। शेष मामले में तिब्बत पूर्ण स्वतंत्र रहेगा। चीन ने भारतीय हितों को भी संरक्षण प्रदान किया। 1954 ई0 में जब चाऊ–एन–लाई भारत आये तो पंचशील के सिद्धन्तो का प्रतिपादन हुआ अैर उन्ही सिद्धांतो के आधार पर भारत सरकार ने उपर्युक्त समझौता को मान्यता प्रदान कर दी। इसके पाँच वर्ष बाद तिब्बत में चीन के विरूद्ध एक विद्रोह (मार्च, 1958 ई0) शुरू हो गया। इस विद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी शासकों ने इस विद्रोह को कुचलना शुरू किया और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। वह भागकर भारत आयें और सरकार ने उन्हे शरण दे दी। चीनी सरकार ने इसे ''शत्रुतापूर्ण कार्य'' बतलाया और भारत पर ''विस्तारवादी'' होने का आरोप लगाया। दोनों ओर से ''शीत–युद्ध'' शुरू हुआ और आरोपों तथा प्रत्यारोपों के कारण दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त बिगड़ गया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पन्त, पुष्पेश एवं जैन, श्री पाल,, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मीनाक्षी प्रकाशन, 2006।
2. प्रसाद, ईश्वरी, अर्वाचीन भारत का इतिहास, इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन प्रा0 लि0, इलाहाबाद, 1986।
3. राव, एम0 चेलापति, आधुनिक भारत के निर्माताः जवाहरलाल नेहरू, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत नई दिल्ली, 2004।
4. शुक्ल, आर0 एल0, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 1989
5. सर्राफ, बसन्त कुमार, भारत और आधुनिक विश्व, लोक चेतना प्रकाशन, जबलपुर, 2001।
6. शर्मा, मथुरा लाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, कालेज बुक डिपो, जयपुर।
7. उपाध्याय, तेजराम, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति, लोक–चेतना प्रकाशन, जबलपुर, 1963।
8. वर्मा, दीनानाथ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995।
9. यादव, आर0एस0, भारत की विदेश नीति, किताब महल, इलाहाबाद, 2004।